an>

Title: Regarding reported lathi-charge on candidates in Delhi for protesting against removal of Hindi and other regional languages in UPSC Examination.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय अध्यक्ष जी, आज पहली बार नहीं बल्कि कई बार इस सदन में आपके माध्यम से इस मामले को उठा चुके हैं और इस मामले पर उस सदन में भी और इस सदन में भी माननीय मंत्री जी के कई बार बयान आए और कई आश्वासन उन्होंने दिये लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ओर माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हम एक सप्ताह के अंदर इस समस्या का निराकरण करेंगे। दूसरी तरफ मंत्री जी जवाब देते हैं कि हम भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं तीसरी ओर जो हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जी की जो आमरण अनशन की विरासत थी, आमरण अनशन पर बैठे हुए छात्रों के साथ लाठीचार्ज करना, उनका जबर्दस्ती आमरण अनशन तुड़वाना, आमरण अनशन टूटने के बाद जब वे छात्र शांतिपूर्वक कैंडिल मार्च करते हैं, तो उस कैंडिल मार्च में दिल्ली में इस कदर कल लाठीचार्ज हुआ कि चाहे नेहरू नगर हो, बत्रा हो, मुखर्जी नगर हो, हर इलाके के अंदर छात्रों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि कौन छात्र कहां है, इसका भी अंदाज नहीं हो रहा है। अंदाज इस बात का भी नहीं लग पा रहा है कि कौन छात्र जिंदा है और कौन छात्र इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुका है। इस बात का भी अंदाज नहीं लग पा रहा है।

जहां एक ओर मोदी जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद हिन्दी को लेकर बहुत सारी बातें शुरु की थीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी का यह कौन सा हिन्दी प्रेम है? हिन्दी की मांग करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज और लाठीचार्ज ही नहीं, कई ऐसे लोग जो हिन्दी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व श्री श्याम रूद्र पाठक जी हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वह किस अस्पताल में हैं? वे जीवित हैं या अपनी जान गवां चुके हैं या कहां पर पुलिस के द्वारा छिपाये गये हैं? यह हालत मोदी जी की हिन्दी प्रेम की सरकार ने कर दी है। इसलिए हम आपसे यह मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए जिन छात्रों पर अन्याय हुआ है और उसमें जो दोषी लोग हैं चाहे वे सरकार में बैठे हुए लोग हैं या अधिकारी हों, उनके खिलाफ ठोस कदम उठाये जाएं
।

दूसरे, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार स्पष्ट करे कि सरकार सी-सैट की परीक्षा प्रणाली जिसको लेकर पूरा सदन और राज्य सभा भी लगातार चिंतित है तथा इस पर बहस और चर्चा हो रही है। सरकार आश्वासन दे रही है लेकिन लगातार आश्वासन असत्य साबित हो रहे हैं। हर आश्वासन में कहा जाता है कि एक हफ्ते के अंदर कर देंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक हफ्ते से कितनी मियाद बढ़ती जाएगी? क्या ये सदन के सत्र खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं या लाठी चार्ज का रवैया है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार स्पष्ट करे। सरकार समय सीमा को स्पष्ट करे और स्पष्ट बताए कि सी-सैट की परीक्षा प्रणाली खत्म होगी या नहीं होगी? हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के मानने और जानने वाले छात्रों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? सदन के अंदर घोषणा होनी चाहिए। कमेटियां बार-बार बनती हैं। कभी मंत्री जी, कभी गृह मंत्री, कभी जितेंद्र जी की अध्यक्षता की बात कही जाती है। कभी यूपीएससी की कमेटी के नाम पर गुमराह करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आपसे अपील है कि सरकार को डायरेक्शन दें। छात्र जान दे रहे हैं। आप ऐसे छात्रों के साथ न्याय करवाएं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था।

माननीय अध्यक्ष : कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया।

श्री राजेश रंजन : मैं सबसे पहले छात्रों के बारे में कहना चाहता हूं। यूपीएससी में परीक्षा देने वाले इन छात्रों की उम्र 25 से 28 साल की है। ये छात्र काफी संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं क्योंकि ये ही छात्र कल को महत्वपूर्ण जिम्मेदार जगह पर जाने वाले हैं। यह सवाल केवल हिंदी भाषा का नहीं है। अगर सबसे अधिक कोई भाषा प्रभावित होगी तो क्षेत्रीय भाषा होगी। सी-सैट मामले में क्षेत्रीय भाषा अत्यधिक प्रभावित होगी तब जाकर भारतीय भाषा प्रभावित होगी। इससे ये सत्ता पक्ष चिंतित नहीं हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है।

दूसरी बात यह है कि जब लगातार छात्र लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। पुलिस की ज्यादती हो रही है। खासतौर से लड़कियों के साथ जो हुआ है, आप इसे यू-ट्यूब पर देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चियों के साथ मारपीट की गई है। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल की घटना है कि पुलिस गलत तरीके से चार बच्चों में से दो बच्चों को उठाकर कहीं ले गई और दो बच्चों को कहीं ले गई। इसके बाद जब इनके घरवाले चार बच्चों को खोजने के लिए निकले और थाने जाने लगे तो पुलिस ने बदर रूप से लाठियां चलाई। इतनी बड़ी घटना घटी है। हजारों-सैंकड़ों छात्र घायल हो गए। तीन विद्यार्थियों का नाम है जो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दो विद्यार्थी लापता हैं। राज्य सभा में कांग्रेस, जदयू, राजद, समाजवादी पार्टी के सदस्यों और भारतीय भाषा से प्रेम रखने वाले नेताओं ने इसकी गंभीर चिंता की है। आदरणीय सोनिया जी, मुलायम जी, खरगे जी और उधर बैठने वाले भारतीय भाषा से प्रेम रखने वाले लोग भी चिंतित हैं। क्या कारण है कि जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कमेटी बना दी गई। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और जितेंद्र जी की बैठक हुई कि दो दिनों के अंदर मामला सुलझा दिया जाएगा। सदन में लगातार मामला उठ रहा है कि एक सप्ताह के अंदर बात हो जाएगी। कभी मनोज तिवारी जी वहां जाकर कहते हैं कि सरकार चिंतित है।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार चिंतित है या नहीं है लेकिन लाठी और गोली जिस तरह से चल रही है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राजनाथ सिंह जी, इस बात की एश्योर करें कि जो छात्र लापता हैं, मां-बाप उनको खोज रहे हैं, वे कहां हैं? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हो गया।

श्री राजेश रंजन : गोलियां चली हैं, बच्चों को पीटा गया, लाठी से मारा गया।...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले भी इस इश्यु को माननीय सदस्यों ने हाउस में रेज किया है, जिसकी आपने अनुमति दी थी। बाद में मंत्री जी, डा. जितेन्द्र सिंह जी ने समाधान भी दिया है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : समाधान नहीं दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लीजिए।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Our effort should be to find a solution. I also feel sorry for the students who are agitating. They are supposed to enter Administrative Services. Keeping their future also in mind the Government has taken this up seriously. The Prime Minister himself has taken interest in this and a Committee has been found to study this and then take a final decision at the earliest. I can only assure you that I will again convey to the hon. Prime Minister the feelings of the Members of the House. Our Members on this side have also agitated about this because this is not a political issue or a partisan issue. There is a system. ...(*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : वहां लाठी, गोली चल रही है। ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : पप्पू जी, आप भी अनुभवी सदस्य हैं। ...(व्यवधान) I will convey the strong feelings of the entire House and see to it that an early decision is

taken in this regard and the same is communicated to the House.

माननीय अध्यक्ष : अब इतना हो गया।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Is there a difference of opinion? ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): There should be a balance. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is our opinion also. It is not a Hindi or non-Hindi issue. It is an issue of regional languages also. Keeping that in mind, a balanced, mutually acceptable solution would be found. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.वी. राजेश को राजेश रंजन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध किया जाता है।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Madam Speaker, I wish to draw the attention of the Union Minister of Commerce and Industry to set up a Silk Park in Arani. This is a long pending and much awaited project for the people of my constituency.

Arani is popularly called the city of silk saris, next to Kanchipuram. It has more than 60,000 population, out of which 35,000 people are into the weaving profession. The very first National Flag of our country hoisted at the Red Fort on the Independence Day was a silk flag which was weaved in Arani. This historical contribution by Arani silk weavers to our motherland needs to be brought to limelight. As we are stepping into our 67th Independence Day, this is a simple and strong request, through this House, to the hon. Minister to fulfil this demand at the earliest.

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कोयला मंत्री जी का ध्यान देश के अंदर बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों (थर्मल पावर) की ओर दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

12.10 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : जिसमें कोयले की कमी होने के कारण बिजली के उत्पादन में भारी कमी आई है। मेरे राज्य मध्य प्रदेश में जहां 24 घंटे घरेलू बिजली अटल ज्योति के नाम पर दिये जाने की व्यवस्था है, किन्तु कोयले की कमी के कारण 500 मेगावाट से अधिक के उत्पादन की कमी आई है और न चाहते हुए भी अघोषित बिजली कटौती के लिए विद्युत मंडल को मजबूर होना पड़ रहा है।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि हम थर्मल पावरों को एडवांस में कोयला नहीं दे पा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में कई ऐसे कोयला ब्लाक हैं, जो राज्य सरकार को एलाट हुए हैं, किन्तु उनमें उत्पादन वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति न होने के कारण नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान) शायद इसी तरह की समस्याएं अन्य जगहों में भी मौजूद हैं। आखिरकार समस्या के समाधान के लिए कोयला मंत्रालय कौन सा कारगर कदम उठाने जा रहा है। ...(व्यवधान)

मेरी सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी थर्मल पावरों को जल्द से जल्द आवश्यकतानुसार कोयला उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डा. किरिट पी. सोलंकी अपने आपको श्री गणेश सिंह के विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत संघ के नये राज्य के गठन की जरूरत का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। ...(व्यवधान) संप्रति भारत संघ में 29 राज्य एवं 7 संघ क्षेत्र हैं। भारतवर्ष दुनिया का बड़ी आबादी वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी कम होते हुए भी वहां राज्यों की संख्या 50 है। देश के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक आवश्यकता होती है। ...(व्यवधान)

देश के अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विशेषता होती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां की जरूरत को वहां की अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से त्वरित एवं निकट से शासन के सुन्दर प्रयास के माध्यम से उन क्षेत्रों को उन्नत बनाया जा सकता है।...(व्यवधान)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 भोजपुरी भाषी जिलों एवं बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, छपरा आदि जिलों को मिलाकर आज पूर्वांचल राज्य का गठन अनिवार्य है। जिसकी राजधानी वाराणसी में हो। पूर्वांचल राज्य की चिर-प्रतीक्षित मांग अब उम्मीदों में बलवती हुई है। पूर्वांचल क्षेत्र के नागरिकों ने पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है।...(व्यवधान)

12.13 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members went back to their seats.

माननीय अध्यक्ष : छेदी पासवान जी, जीरो ऑवर में पढ़ते नहीं हैं, आप मुद्दा उठाइये, बस आपकी बात पूरी हो गई।

श्री छेदी पासवान : अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भोजपुरी भाषा-भाषी जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य का गठन कराने की कृपा करें।